गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 208
दि. 29.11.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वोट पड़ेंगे, जीत भी मिलेगी—लेकिन कुर्सी का फ़ैसला अदालत करेगी,महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, चुनाव की मंजूरी पर नतीजों पर रोक

(जीएनएस)। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर लगातार चल रहा गतिरोध आखिर सुप्रीम कोर्ट की दखल से थोड़ा साफ हुआ है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट अभी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में निकाय चुनाव कराने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन मतदान के बाद नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे। लोगों की लंबी प्रतीक्षा के बाद लौटे चुनाव अब एक नई उलझन के साथ आगे बढ़ रहे हैं—मत पड़ेंगे, जीत-हार तय होगी, लेकिन कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला अदालत की अगली सुनवाई में होगा।

दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने गुरुवार को यह महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए साफ कर दिया कि 50% से अधिक आरक्षण वाले किसी भी निकाय का भाग्य ओबीसी आरक्षण से जुड़ी लंबित याचिकाओं के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा। अदालत ने कहा कि चुनाव रोकने का कोई कारण नहीं है, लेकिन परिणामों को सुरक्षित रखा जाएगा। यानी यह एक अस्थायी ढांचा है, जो अदालत के अंतिम फैसले तक चलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण वाले निकायों पर तत्काल प्रभाव से नई अधिसूचनाएं जारी करने पर रोक लगा दी है। जहां अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है, वहां मतदान तो होगा लेकिन नतीजे घोषित नहीं होंगे। दो महानगरपालिकाओं पर भी यही नियम लागू रहेगा। अदालत ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले को बड़ी बेंच—तीन जजों—के पास भेज

दिया है, जो 21 जनवरी 2026 को अंतिम सुनवाई करेगी। उसी सुनवाई से तय होगा कि इन निकायों के चुनाव के परिणाम मान्य होंगे या नए सिरे से चुनाव की नौबत आएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि 246 नगरपालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2 दिसंबर को मतदान होना है। इनमें से 40 नगरपालिका परिषदें और 17 नगर पंचायतें ऐसी हैं, जहाँ आरक्षण 50% से अधिक है। अदालत ने कहा कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन सभी नतीजे अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेंगे।

सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग ने आशंका जताई थी कि यदि अदालत स्पष्ट निर्देश नहीं देगी तो चुनाव प्रक्रिया फिर टल सकती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले के आदेश पर्याप्त हैं, फिर भी अदालत लिखित आदेश में यह सुनिश्चित कर रही है कि जिन जिला परिषदों व पंचायत समितियों में आरक्षण 50% से कम है, वहां चुनाव पहले की तरह होंगे, लेकिन इनके परिणाम भी अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अदालत यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर कर रही है ताकि चुनावों में और देरी न हो।

सुनवाई के दौरान एक अहम पल तब आया जब राज्य ने कहा कि सिर्फ दो महानगरपालिकाओं में आरक्षण 50% की सीमा पार कर सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने गहरी टिप्पणी की कि "जो भी किया जाता है, समाज को जाति की रेखाओं में नहीं बांटना चाहिए।" अदालत की यह टिप्पणी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रह सकती है।

इस बीच राज्य में 2 दिसंबर का मतदान निश्चित है। हजारों उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनकी जीत-हार अदालत की अगली सुनवाई तक अधर में अटकी रहेगी। मतदाता मतदान केंद्रों पर जाएंगे, अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनेंगे, लेकिन मतगणना का राजनीतिक रंग तभी उजागर होगा जब सुप्रीम कोर्ट 21 जनवरी को अंतिम फैसला सुना देगा।

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव दिसंबर 2021 से रोक पर थे। ओबीसी आरक्षण के 'ट्रिपल टेस्ट' को पूरा किए बिना आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता—सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने राजनीतिक समीकरण में भारी उथल-पुथल मचा दी थी। बंठिया आयोग की रिपोर्ट आई, फिर कई बार सरकार और आयोग के तर्कों पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की। अब कई वर्षों की कानूनी बहस और राजनीतिक गतिरोध के बाद चुनाव की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन निर्णय की अंतिम गाड़ी अदालत के गलियारे में ही अटकी है।

यह संभव है कि कुछ उम्मीदवार चुनाव जीतकर भी कुर्सी तक न पहुँच सकें। कुछ हारने वाले भविष्य में फिर से मौके पा सकते हैं। कई सीटों का भाग्य सिर्फ अदालत के अंतिम निर्णय पर टिका रहेगा। यह भी संभव है कि अदालत कुछ सीटों पर चुनाव दोबारा कराने का आदेश दे दे, या मौजूदा आरक्षण ढांचे के अनुसार ही परिणाम लागू हो जाएँ।

फिलहाल महाराष्ट्र पूर्ण अनिश्चितता के दौर में है—जनता मतदान के लिए तैयार है, उम्मीदवार प्रचार में जुटे हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यह अब जनता नहीं बल्कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा।

दिल्ली-मुंबई यात्रा आधी होगी, नया एक्सप्रेसवे बस 12 घंटे में जोड़ेगा राजधानी और आर्थिक राजधानी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और पूरा होने के बाद राजधानी और वित्तीय राजधानी के बीच यात्रा का समय आधा होकर सिर्फ 12 घंटे रह जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में सूरत में परियोजना के गुजरात सेक्शन का निरीक्षण करते हुए पत्रकारों को बताया कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और सभी छोटी-मोटी कमियों को दूर किया जा रहा है ताकि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिल सके। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क मार्ग नहीं है, बल्कि यह आधुनिक यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एक संपूर्ण परियोजना है।

गडकरी ने विस्तार से बताया कि पूरा एक्सप्रेसवे आठ लेन का होगा, जिससे यात्रा का समय वर्तमान 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रह जाएगा। इसके किनारों पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए

जाएंगे, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सड़क यात्रा के अनुभव को भी बेहतर बनाएंगे। परियोजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को निर्बाध, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीक और निर्माण पद्धतियों के कारण इस एक्सप्रेसवे की लंबी उम्र और स्थायित्व सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही इसकी लागत को नियंत्रित रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित नहीं रहेगी। गडकरी ने बताया कि पूरा होने पर यह मार्ग उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी जुड़ेगा, जिससे इन राज्यों के लोगों को दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक आसान और तेज़ पहुंच मिलेगी। उन्होंने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी कहा कि इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक भी चल सकते हैं, जिससे सड़क परिवहन का आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल स्वरूप विकसित होगा। वडोदरा से मुंबई तक के 379 किलोमीटर लंबे हिस्से का काम अंतिम चरण में है और अगले साल के अंत तक इसे पूरी तरह खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

यह लिंक पूरे 1359 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है और विरार मार्ग के जरिए पूरे रूट से जुड़ता है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की नींव 2019 में रखी गई थी और तब से इसका निर्माण लगातार प्रगति पर है।

गडकरी ने यह भी कहा कि इस परियोजना से न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने से देश के सड़क परिवहन ढांचे में एक नया अध्याय शुरू होगा और यह परियोजना सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, पर्यावरण और सुविधा के क्षेत्र में मिसाल साबित होगी। राजधानी और आर्थिक राजधानी के बीच यात्रा अब पहले से कहीं अधिक तेज़, सुरक्षित और आरामदायक होने जा रही है, और यह सड़क परियोजना भारतीय सड़क परिवहन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने जा रही है।

नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का बड़ा बयान, "जरूरत पड़ी तो गरीबों के लिए आधी रात तक खुले रहेंगे दरवाज़े", न्याय प्रणाली में संवेदनशील बदलाव की उम्मीद

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पदभार ग्रहण करते ही न्याय प्रणाली को आमजन के और करीब लाने का संदेश दिया है। शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने अदालत के भीतर मौजूद सभी लोगों को चौंका भी दिया और भरोसे से भी भर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब, वंचित और हाशिए पर खड़े लोगों को न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे उनके लिए आधी रात तक अदालत में बैठने को तैयार हैं।

यह टिप्पणी उन्होंने तिलक सिंह डांग की एक याचिका को खारिज करते हुए की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, "ऐसे मामले अक्सर संपन्न वर्ग के लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहां सबसे छोटे और सबसे गरीब व्यक्ति की लड़ाई सुनने के लिए हूं। अगर वह व्यक्ति मेरे सामने न्याय की उम्मीद लेकर आएगा, तो मैं देर रात तक उसकी याचिका सुनने में भी संकोच

नहीं करूंगा।" न्यायमूर्ति सूर्यकांत के इस बयान ने अदालत के भीतर मौजूद हर व्यक्ति को न्याय की मूल भावना की याद दिला दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं। हरियाणा के हिसार के एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से निकलकर देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक पहुंचने वाली उनकी यात्रा स्वयं यह संदेश देती है कि न्याय व्यवस्था में संवेदनशीलता और संवाद का कितना महत्व है। वे लगभग 15 महीनों तक इस पद पर रहेंगे और 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। उनके इस स्पष्ट रुख ने न्याय तक समान पहुंच की बहस में एक नई उम्मीद जगाई है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का एक और महत्वपूर्ण विषय बुधवार को सामने आया, जब राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को देश के विभिन्न राज्यों में लागू समान कानूनों के खिलाफ दायर अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) सहित अन्य संगठनों की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि कानून के कई प्रावधान मनमाने और असंवैधानिक हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने अदालत को बताया कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 25 और 26 का उल्लंघन करता है, क्योंकि नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने का मौलिक अधिकार है।

राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएजी शिवमंगल शर्मा ने सुनवाई के दौरान अदालत को देशभर में मौजूद ऐसे धर्मांतरण विरोधी कानूनों और उनसे जुड़ी ट्रांसफर याचिकाओं की विस्तृत सूची सौंपी। इस मामले को अब तक चौथी बार शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बयान और अदालत में चल रही संवैधानिक बहस—दोनों मिलकर यह दर्शाते हैं कि आने वाले समय में न्यायपालिका सक्रिय, संवेदनशील और जनउन्मुख भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

अब भारत में होगी MH-60R हेलीकॉप्टरों की मरम्मत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की सामरिक शक्ति में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए भारत सरकार ने अमेरिका के साथ लगभग 7,995 करोड़ रुपये के व्यापक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद एमएच-60आर 'सीहॉक' हेलीकॉप्टरों की मरम्मत और रखरखाव की पूरी प्रक्रिया अब भारत में ही की जा सकेगी। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस करार पर हस्ताक्षर करते हुए दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग के नए दशक की नींव रखी। इस परियोजना के तहत अगले पाँच वर्षों तक इन हेलीकॉप्टरों के लिए रिपेयर, परीक्षण, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट, रिप्लेसमेंट, सपोर्ट इक्विपमेंट और भारत में इंटरमीडिएट लेवल रिपेयर सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यह कदम नौसेना की ऑपरेशनल उपलब्धता को तेज गति देगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा क्षेत्र की प्रगति को नई मजबूती प्रदान करेगा।

भारतीय नौसेना ने फरवरी 2020 में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 24 एमएच-60आर हेलीकॉप्टर खरीदने का लगभग 2.6 अरब डॉलर का सौदा किया था। अब तक इनमें से 19 हेलीकॉप्टर भारत पहुंच चुके हैं और पिछले वर्ष आईएनएस गरुड़, कोच्चि में इनकी पहली स्क्वाड्रन को आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जा चुका है।

एमएच-60आर को दुनिया का सबसे सक्षम मल्टी-मिशन समुद्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। अत्याधुनिक सेंसर, एडवांस्ड एवियोनिक्स और पनडुब्बी-रोधी हथियारों से लैस यह हेलीकॉप्टर समुद्री निगरानी, एंटी-सबमरीन मिशन, खोज-बचाव और कई रणनीतिक अभियानों में नौसेना की रीढ़ बन चुका है।

हरिद्वार कुंभ 2027 को दिव्य–भव्य रूप देने की तैयारी तेज, प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियां घोषित—गंगा तट पर संतों संग बैठकर मुख्यमंत्री धामी ने खींची आयोजन की रूपरेखा

(जीएनएस)। हरिद्वार। पवित्र हरिद्वार में वर्ष 2027 का महाकुंभ अब पूरी तरह से अपनी तैयारी की ओर बढ़ चला है। गंगा तट पर शुक्रवार को एक ऐतिहासिक दृश्य उस समय बना जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखाड़ा परिषद के सभी 13 अखाड़ों के संतों के साथ विस्तृत बैठक कर न केवल प्रमुख स्नान की तिथियों की घोषणा की, बल्कि कुंभ 2027 के दिव्य, भव्य और व्यापक आयोजन का संकल्प दोहराया।

हरिद्वार का कुंभ न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर का ज्वलंत प्रतीक भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तैयारी का खाका समय से पहले तैयार करना शुरू कर दिया है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कुंभ के प्रमुख स्नान पर्वों की औपचारिक घोषणा की। जनवरी से अप्रैल तक फैलने वाले इस विराट आयोजन में लाखों की भीड़ हर स्नान पर्व पर उमड़ेगी। घोषित तिथियां इस प्रकार रहेंगी—

14 जनवरी को मकर संक्रांति, 6 फरवरी को मौनी अमावस्या, 11 फरवरी को वसंत पंचमी, 20 फरवरी को माघ पूर्णिमा, 6 मार्च को महाशिवरात्रि का अमृत स्नान, 8 मार्च को फाल्गुन अमावस्या का अमृत स्नान, 7 अप्रैल को नव संवत्सर, 14 अप्रैल को मेष संक्रांति का अमृत स्नान, 15 अप्रैल को श्रीराम नवमी और 20 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का पवित्र स्नान सम्पन्न होगा।

इन तिथियों के साथ कुंभ 2027 की रूपरेखा अब आधिकारिक रूप से तय हो चुकी है।

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में कहा कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड को "विश्व की आध्यात्मिक राजधानी" बनाने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए कुंभ 2027 को हर दृष्टि से ऐतिहासिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2021 का कुंभ कोविड प्रतिबंधों के कारण सीमित स्वरूप में रह गया था, लेकिन इस बार हरिद्वार कुंभ को वैश्विक स्तर पर उदाहरणीय बनाने का लक्ष्य है। श्रद्धालुओं की संख्या पिछले कुंभों की तुलना में कई गुना अधिक होने की संभावना है और उसी अनुरूप तैयारियां भी की जा रही हैं।

बैठक में सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख मुद्दों में रही। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य पुलिस, एनडीआरएफ, पीएसी, स्वास्थ्य विभाग और फायर सेवाएं संयुक्त रूप से एक विशेष समन्वय तंत्र के तहत काम करेंगी। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, आपात योजनाएं, स्वच्छता मिशन और घाटों की सुरक्षा—हर बिंदु पर विशेष टीमों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2010 और 2021 के कुंभ का अनुभव रखने वाले अफसरों की मदद से इस बार आयोजन को और अधिक सुनियोजित बनाया जाएगा, ताकि कोई भी व्यवस्था भीड़ के बोझ से चरमराए नहीं।

संत समाज ने मुख्यमंत्री की पहल की सराहना की। बैठक में उपस्थित विभिन्न अखाड़ों के महंतों और आचार्यों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय रहते तैयारी शुरू करना स्वागतयोग्य है और संत समुदाय कुंभ 2027 को भव्य आयाम देने में पूरा सहयोग करेगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने संतों के साथ भोजन कर इस आध्यात्मिक संवाद को और अधिक सौहार्दपूर्ण बनाया।

बैठक में सांसद कल्पना सैनी, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा, हरिद्वार व रुड़की की महापौर, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद सहित कई प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित रहे।

कुंभ 2027 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और हरिद्वार अब एक बार फिर दुनिया भर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी में जुट चुका है।

संपादकीय

भयावह जलवायु संकट

ब्राजील के बेलेम में संपन्न कॉप-30 सम्मेलन में जारी 'जलवायु जोखिम सूचकांक-2026' रिपोर्ट में उल्लेखित आंकड़े भारत से जुड़ी जलवायु संकट की भयावह तस्वीर दिखाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया में जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित पहले दस देशों में शामिल हैं। यह डराने वाली रिपोर्ट बताती है कि पिछले तीन दशक में भारत में आई जलवायु संकट से जुड़ी आपदाओं में करीब अस्सी हजार लोगों को मौत का ग्रास बनना पड़ा। इतना ही नहीं करीब 170 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान भी देश को उठाना पड़ा है। ये आंकड़े जलवायु संकट के देश पर पड़ने वाले घातक प्रभावों की तस्वीर उकेरते हैं। जो बताते हैं कि इस संकट से उबरने के प्रयासों में और तेजी लाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर इस दिशा में यदि युद्ध स्तरीय प्रयास तेज नहीं किए जाते तो भविष्य में परिणाम और घातक हो सकते हैं। ये प्रयास केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी तेज करने की जरूरत है। जागरूकता अभियानों में भी तेजी लाने की जरूरत है। इस संकट ने फसलों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव से हमारी खाद्य शृंखला पर भी संकट मंडरा सकता है। हमें 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का पेट भरने के लिये इस दिशा में शोध-अनुसंधान के साथ व्यापक किसान जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने की जरूरत है। दरअसल, जलवायु संकट के चलते देश में जो ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके पीछे लगातार आ रहे चक्रवात, कुछ इलाकों में सूखे और बाढ़ की लगातार पैदा होती स्थितियां हैं। जाहिर इसके मूल में तेजी से बढ़ता वातावरण का तापमान ही है। जिसका मुख्य कारक ग्लोबल वार्मिंग ही है। निश्चित रूप से भारत में जलवायु संकट की स्थिति लगातार विकट होती जा रही है। निर्विवाद रूप से देश के सामने पैदा मौसमी आपदाओं से हमारे विकास में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। जो जीविका संकट भी पैदा कर रहा है। दरअसल, बेलेम में संपन्न कॉप-30 सम्मेलन में जारी की गई 'जलवायु जोखिम सूचकांक-2026' रिपोर्ट उन संकटपूर्ण स्थितियों का भी खुलासा करती है जो जलवायु संकट के कारण पैदा हो रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि पिछले वर्ष भारी बारिश व विनाशक रूप में आई बाढ़ से देश में करीब अस्सी लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसमें दो राय नहीं कि भारत सरकार ने जलवायु संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष अपनी प्रतिबद्धता बार-बार जतायी है। इस संकट से उबरने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्प को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया है। देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में नवीकरणीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। देश वनों का दायरा को भी बढ़ाने की जरूरत है। विकास देश की प्राथमिकता है, लेकिन यह विकास वनों के विनाश की कीमत पर नहीं होना चाहिए। साथ ही इस दिशा में जो भी कदम उठाये जाएं उनका प्रभाव जमीनी स्तर पर कितना हो रहा है, इस बात का लगातार मूल्यांकन भी जरूरी है। साथ ही रीति-नीतियों को प्रभावी तरीकों से अमलीजामा पहनाने की जरूरत होगी। जिसके लिये लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाइयों ग्राम पंचायत से लेकर शहरी निकायों को भी शामिल करने की जरूरत होगी। दरअसल, जलवायु परिवर्तन से उपजा संकट केवल भारत की ही चुनौती नहीं है। यह एक वैश्विक संकट है। जो इस बात से पता चलता है कि पिछले तीन दशकों में नौ हजार से अधिक मौसमी आपदाओं ने पूरी दुनिया में आठ लाख से अधिक लोगों को असमय काल का ग्रास बनाया है। लेकिन इस संकट की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इसकी सबसे बड़ी कीमत वे विकासशील व गरीब देश चुका रहे हैं, जिनकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सबसे कम भूमिका रही है। दुर्भाग्य से विकासशील देश जहां इन संकटों की दृष्टि से जहां ज्यादा संवेनशील हैं, वहीं इससे मुकाबले के लिये उनके संसाधन सीमित हैं। उनके प्रतिरोध की क्षमता सीमित है। जिन्हें तत्काल व्यापक वित्तीय सहायता की जरूरत है। ऐसे में विकसित देशों का नैतिक दायित्व बनता है कि उनका सहयोग सिर्फ विकासशील देशों को वित्तीय व तकनीकी सहयोग तक सीमित न रहे। साथ ही वे अपने कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाएं।

मौलिक कर्तव्यों के पालन से कर्मयोग की राह

> "मौलिक कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण भारत में नागरिक उदासीनता बढ़ी है, जो स्वच्छता की कमी और सार्वजनिक संपत्ति की उपेक्षा जैसी समस्याओं में परिलक्षित होती है।

आज़ादी ने हमें अधिकार दिए, मगर हमने कर्तव्य भुला दिए? यही असंतुलन आज भारत की सबसे बड़ी नैतिक चुनौती है। सदियों की गुलामी के बाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ज़रूरी था। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि सिर्फ़ अधिकारों पर ज़ोर देने से एक स्वस्थ और सक्रिय समाज नहीं बन सकता। एक ऐसा राष्ट्र, जो केवल अपने अधिकारों की मांग करता हो, मगर अपने कर्तव्यों को भूल जाए, वह नागरिक उदासीनता और व्यवस्थागत विफलताओं का शिकार हो जाता है।

यह उदासीनता श्रीमद्भगवद्गीता के 'स्व-धर्म' सिद्धांत का उल्लंघन है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने पर ज़ोर देता है। जब नागरिक यह मान लेते हैं कि समस्याओं को नेता या अधिकारियों द्वारा हल किया जाएगा, तो वे पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे अपने मौलिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी से भागते हैं। मौलिक कर्तव्य इस पलायनवाद का मुकाबला करने और नागरिक को यह याद दिलाने के लिए एक कानूनी-नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं कि सामूहिक प्रगति उनकी आत्म-अनुशासित कार्रवाई पर निर्भर करती है।

इसी असंतुलन को दूर करने के लिए, 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) के माध्यम से संविधान में भाग चार-ए और अनुच्छेद 51ए को जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। बाद में 86वें संशोधन (2002) में शिक्षा के अधिकार से जुड़ा एक और कर्तव्य (51ए(के)) जोड़ा गया। ये मौलिक कर्तव्य अक्सर सिर्फ़ 'नैतिक उपदेश' मानकर नज़रअंदाज़ कर दिए जाते हैं क्योंकि इन्हें सीधे तौर पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यह नज़रिया अधूरा है। ये 11 मौलिक कर्तव्य वास्तव में भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए 'निष्काम कर्म' उपदेशों का ही रूप हैं। ये कर्तव्य हमें सिखाते हैं कि राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व ही हमारा 'धर्म' है। भगवद्गीता का 'निष्काम कर्म' (फल की इच्छा के बिना कर्तव्य करना) भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा करने

के लिए एक आवश्यक मनोवैज्ञानिक इंजन प्रदान करता है। गीता का सूत्र—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः' सिखाता है कि उत्कृष्टता (अनुच्छेद 51(ए)(जे)) केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब नागरिक पुरस्कार या इनाम के लालच के बिना ये केवल कर्तव्य के लिए कार्य करते हैं। उत्कृष्टता 51(ए(जे))का कर्तव्य सीधे निष्काम कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है, जो फल की चिंता किए बिना अपने कार्य को कुशलता और समर्पण के साथ करने पर ज़ोर देता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा (51ए(आई)) गीता के अध्यात्म ज्ञान (पदार्थ की नश्वरता) से प्रेरित है। यह ज्ञान भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव और अहंकार को कम करता है, जिससे नागरिक सार्वजनिक संपत्तियों को 'मेरा' मानकर उनकी सुरक्षा का दायित्व लेते पर्यावरण की रक्षा (51ए(जी)) का उपदेश लोकमंगल का आधुनिक रूप है। यह सभी जीवों के प्रति एक नैतिक दायित्व को स्थापित करता है, जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना (51ए (एच)) आध्यात्मिक विवेक (तर्क और सही-गलत का भेदभाव) का धर्मनिरपेक्ष रूप है।

असम के जादव पायेंग, जिन्हें 'फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया' के नाम से जाना जाता है, निष्काम कर्म के माध्यम से संवैधानिक उद्देश्यों को ज़मीन पर उतारने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1979 में, बाढ़ के बाद सांपों को गर्मी से मरते हुए देखने के दुखद अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता एक बंजर रेतीले टीले पर बांस के पौधे लगाना शुरू कर दिया। दशकों के अथक और निस्वार्थ प्रयास का परिणाम आज मोलाई जंगल है, जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है। उनका यह कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए(जी) पर्यावरण की रक्षा और 51ए(जे) का जीवंत प्रमाण है। शिक्षा का उद्देश्य केवल मौलिक कर्तव्यों का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे 'कर्म योग' के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए, सामुदायिक सेवा को एक अनिवार्य 'नागरिक कर्म योग' परियोजना के रूप में लागू किया जाना चाहिए, जो सीधे पर्यावरण की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और सामाजिक भाईचारे जैसे कर्तव्यों को बढ़ावा दे। पाठ्यक्रम में सभी विषयों के साथ मौलिक कर्तव्यों का विषय-आधारित एकीकरण किया जाना चाहिए- जैसे विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पढ़ाना। छात्रों में समालोचनात्मक सोच और 'विवेक' विकसित करने के लिए तर्क-आधारित वाद-विवाद और मीडिया साक्षरता को अनिवार्य किया जाए। शिक्षकों को नैतिक मूल्यों के मार्गदर्शक के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

भारत को उसके उच्चतम नैतिक और सामाजिक स्तर तक पहुंचाने का एकमात्र मार्ग यही है कि मौलिक कर्तव्यों को केवल किताबों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें हमारे दैनिक जीवन का 'कर्म योग' बनाया जाए। यह समय है कि हम अर्जुन बनें और अपने जीवन में संवैधानिक कर्म योग का पालन करें।

प्रेरणा

जीवन के अनगिनत चेहरे और उनसे मिली अनदेखी सीखें

मानव जीवन एक विस्तृत नदी की तरह है, जिसमें हर मोड़ पर, हर धार में और हर लहर के नीचे कोई न कोई सीख छिपी रहती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ज्ञान केवल बड़े ग्रंथों में मिलता है, कि समझ केवल मंचों पर बोलने वाले विद्वानों के पास होती है, और कि जीवन की दिशा वही तय करते हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज होते हैं। पर सच यह है कि जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ हमें वहीं मिलते हैं जहाँ हम हर दिन जीते हैं—लोगों की छोटी-छोटी आदतों में, उनके व्यवहार की झलकियों में, और उन क्षणों में जो देखते ही देखते बीत जाते हैं, पर भीतर अपनी छाप छोड़ जाते हैं।

इसी अनुभव का एक अद्भुत वर्णन दार्शनिक अरस्तू ने किया, जब एक दिन उनसे पूछा गया कि आपने जीवन में किन महान लोगों से सीख ली। प्रश्न पूछने वाला यह उम्मीद कर रहा था कि अरस्तू प्राचीन विद्वानों, दार्शनिक गुरुओं या राज्य के उच्च व्यक्तियों के नाम बताएँगे। पर अरस्तू की मुस्कान में जो शांति थी, वह यह बताने के लिए काफी थी कि उत्तर किसी और ही दिशा में जाएगा।

उन्होंने शांत स्वर में कहा कि उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रसिद्ध या विद्वान व्यक्ति से सीखने का दावा कभी नहीं किया। बल्कि उनकी सारी शिक्षाएँ उन साधारण इंसानों से आईं, जिनसे वे प्रतिदिन रूबरू होते थे। वह भी इसलिए नहीं कि वह लोग आदर्श थे, बल्कि इसलिए कि उनके दोष

ही उनके लिए गुरु बन गए। अरस्तू का यह स्वीकारना अपने आप में एक गहरी दार्शनिक दृष्टि था—कि जीवन में अच्छाई और सीख अक्सर बुराई और गलत आचरण के पर्दे के पीछे छिपी होती है। उन्होंने बताया कि कपटी लोगों से उन्होंने ईमानदारी को पहचाना। किसी के छल को देखने के बाद ही सत्य का महत्व भीतर गहरा जमता है। जब लोग कृपण होते हैं, तो उदारता का स्वाद और मीठा लगता है। बातूनी लोगों का सतत बोलना हमें मौन की सुंदरता याद दिलाता है—वह मौन, जो शब्दों से अधिक गहन होता है। असहिष्णु लोगों से उन्होंने धैर्य का महत्व जाना। जब कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता, तब हमें यह समझ आता है कि सहनशीलता कितनी जरूरी है। जब किसी की निर्दयता सामने आती है, तब दिल में करुणा का दीपक जलता है। और जब कोई जल्दबाज़ी में बिना सोचे-समझे निर्णय कर लेता है, तो समझ आता है कि ठहराव और धीरज कितनी बड़ी शक्ति हैं, जो जीवन को सही दिशा दे सकती हैं।

अरस्तू का यह अनुभव केवल उनका नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जागरूक होकर जीवन को देखता है। वे साधारण लोग, जिनसे हम कभी-कभी चिढ़ते हैं, जिन्हें हम गलत समझते हैं, जिनकी आदतों से हम परेशान रहते हैं—वे ही लोग अनजाने में हमारे शिक्षक बन जाते हैं। उनकी कमियाँ हमारे लिए दर्पण बनती हैं, जिसमें हम अपनी अच्छाई को पहचानते हैं।

जीवन की यह अद्भुत कला ही इसे जीवंत और रहस्यमय बनाती है। हर दिन, हर क्षण, हर मुलाकात सीख का एक नया द्वार खोलती है। एक छोटी-सी घटना, एक छोटी-सी चूक, एक छोटी-सी बातचीत—ये सब मिलकर हमें वही बनाते हैं जो हम आगे चलकर बनते हैं। कभी किसी की गलती हमें बेहतर बनाती है, कभी किसी का गलत व्यवहार हमें सही दिशा दिखाता है, और कभी किसी की कठोरता हमारे भीतर दया के नए स्रोत खोल देती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे अनोखा विद्यालय वही है, जिसमें हम हर पल मौजूद हैं। लोग चाहे जैसे हों—कठोर, कपटी, कृपण, अहंकारी या असहिष्णु—वे सभी हमारे मार्ग पर छोटे-छोटे दीपक बनकर आते हैं। सीखने वाला ही वह दीपक देख पाता है, जो दूसरों की नजरों से ओझल रहता है। जीवन एक निरंतर यात्रा है और दुनिया एक अनंत कक्ष। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव एक शिक्षक है, और हम उसके विद्यार्थी। जो यह समझ लेता है, उसके लिए जीवन का हर दिन एक नया पाठ बन जाता है, एक नई जागृति, एक नई रोशनी।

आखिर भारतीय संविधान से अपेक्षित मौलिक संशोधन कबतक? समझिए कितने हैं जरूरी?

भले ही भारतीय संविधान ने देश-काल-पात्र के परिप्रेक्ष्य में हम भारतीयों को बहुत कुछ दिया है, फिर भी इससे और अधिक लेने की अपेक्षा रखना लाजिमी है। इस दिशा में सुलगता हुआ सवाल यही है कि आखिर सिस्टम पर विगत लगभग आठ दशकों से कुंडली मार कर बैठने वाले लोगों या उनके उत्तराधिकारियों-परिजनों ने, जिसमें संविधान की आरक्षण व्यवस्था द्वारा पैदा किये हुए राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक और मीडियागत के 'अभिजात्य वर्गों' के विधिक शोषण से उनके ही वर्ग या समाज के संघर्षरत अन्य लोगों को आखिर मुक्ति कब तक मिलेगी! इतना ही नहीं, नियम कानून द्वारा इस देश में असली समाजवाद, समानतावाद और समरसतावाद कब तक लाया जाएगा? वहीं, पूरी व्यवस्था पर हावी होते परिवारवाद और सम्पर्कवाद को कब और कैसे हतोत्साहित किया जाएगा? चाहे अल्पसंख्यक वाद हो या पंथनिरपेक्षता/धर्मनिरपेक्षता का सवाल, इसे व्यवहारिक अमलीजामा कब तक पहनाया जाएगा? वहीं, पाकिस्तान-बंगलादेश के मुकाबिल इसे तुलनात्मक रूप से कबतक लागू करवाया जाएगा?

खास बात यह कि इस दिशा में सहयोगी साबित हो रहे द्विअर्थी कानूनों को आखिर कैसे और कबतक बदला जाएगा? वहीं, बहुमतधारी राजनेताओं द्वारा अल्पमत का धड़ल्ले से किये जा रहे उत्पीड़न को आखिर कैसे रोका जाएगा? वहीं, योग्यता के ऊपर अयोग्यता को कबतक थोपा जाता रहेगा? क्योंकि किसी भी सभ्य व सुसंस्कृत समाज में ऐसी विधिक विडंबनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा और मेरे जैसे लोगों का स्पष्ट मानना है।

साथ ही, पेशेवर संस्थाओं को भी क्षुद्र सियासत के मकड़जाल से शीघ्र मुक्त करवाना भी बदलते वक्त की मुखर मांग है, ताकि नीतिगत घालमेल को रोका जा सके। यही वजह है कि भारतीय संविधान में व्यापक सुधार के लिए कतिपय प्रमुख संशोधन बहुत जरूरी समझे जा रहे हैं।प्रासंगिक सवाल है कि आखिर भारतीय संविधान से अपेक्षित मौलिक संशोधन कबतक होंगे? यहां पर विस्तार पूर्वक समझिए कि ये अब कितने जरूरी बन चुके हैं? क्योंकि कानूनी स्थितियों के लाभ उठाते हुए कुछ अमीर लोग भी वास्तविक दलितों-पिछड़ों के हक मार रहे हैं। इसलिए कतिपय संवैधानिक सुधार बहुत जरूरी समझे जाते हैं। दरअसल, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि वर्तमान समय की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के अनुरूप पूछा जा सके। संशोधन प्रक्रिया में लचीलापन बढ़ाकर संविधान को और अधिक सामयिक बनाया जा सकता है। तत्सम्बन्धी बहुमूल्य सुझावों पर गौर किया जाना चाहिए, जिनमें निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं:-

पहला, संविधान में संशोधन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाना चाहिए, ताकि राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जा सके। संवैधानिक संशोधनों में नागरिक समाज और विभिन्न दलों की भागीदारी सुनिश्चित हो। वहीं, नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में और मजबूती देने तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को बेहतर तरीके से संवैधानित किया जा सके।

दूसरा, मौलिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना जरूरी बताया गया है, साथ ही नागरिक स्वतंत्रताओं को मजबूत करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सुधारा जाना चाहिए। संविधान के मूल ढांचे की रक्षा के साथ-साथ वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों में सुधार आवश्यक है, जैसे कि मौलिक अधिकारों का सशक्तीकरण एवं आपातकालीन प्रावधानों की सीमाओं का पुनः मूल्यांकन। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक नैतिकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से संवैधानिक नैतिकता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका सुधारों की मांग है, ताकि संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण प्रभावी तरीके से हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों को मजबूत करना, साथ ही न्यायालयों की कार्यप्रणाली को तीव्र और प्रभावी बनाना आवश्यक है।

चतुर्थ, संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान हो सके और केंद्र के अतिक्रमण को रोका जा सके। संघीयता के संतुलन को सुधारने हेतु केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पुनर्वितरण आवश्यक है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता और निर्णायक शक्तियाँ बढ़ सकें तथा संघीय संकट कम हो। पंचम, सामाजिक न्याय और समावेशन के लिए विशेष वर्गों के अधिकारों की पुनः समीक्षा, जिससे वे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप रहें और सामाजिक एकता बनी रहे।

छठा, डिजिटल युग में संविधान की प्रासंगिकता बनाए रखने हेतु नई तकनीकों को ध्यान में रखते हुए डेटा सुरक्षा, निजता और सूचना के अधिकार जैसे विषयों पर नए प्रावधान शामिल किए जाएं।

सप्तम, आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक व्यवस्था में स्पष्ट और सीमित प्रावधान रखने की सलाह दी जाती है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा हो सके।

मेरा स्पष्ट मानना है कि ये बहुमूल्य सुझाव भारतीय संविधान को अधिक गतिशील, समावेशी और समय के साथ विकसित होते रहने वाला दस्तावेज बनाएंगे, जिससे यह देश के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए बेहतर कार्य करेगा। ये सुझाव संविधान की गतिशीलता और प्रभावशीलता बढ़ाने के साथ ही लोकतांत्रिक और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक माने जा रहे हैं।

अभियान

सावन की पावन वर्षा में संतान सुख का दिव्य आशीर्वाद

सावन का महीना आते ही ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं किसी अदृश्य भक्ति-राग में डूब गई हो। हवा में शीतलता बढ़ जाती है, मिट्टी की महक मन को शांत करने लगती है, और हर ओर हरियाली ऐसे उगती है जैसे किसी ने धरती पर आशीर्वाद बरसा दिया हो। इसी पवित्र माहौल में सोमवार का दिन विशेष चमकता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती का होता है—वह दिव्य युगल जो सृष्टि, पालन और कल्याण का आधार माना जाता है।

कहते हैं कि सावन सोमवार केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि उन मनोकामनाओं के पूरे होने का समय है जो दिल के भीतर वर्षों से दबी रह जाती हैं। कई दंपति, जिनके जीवन में संतान की किलकारी अभी तक नहीं गूँजी, इस दिन शिव-पार्वती की शरण में जाते हैं। उनकी आंखों में एक उम्मीद, एक विश्वास और एक शांत विनती होती है—कि प्रभु उनके जीवन में भी मातृत्व तथा पितृत्व का आनंद भरें।

सदियों से चली आ रही मान्यता बताती है कि सावन सोमवार के दिन की गयी पूजा विशेष फलदायी होती है। यह वह

समय है जब देवत्व और धरती के बीच का आवरण हो जाता है और मन की प्रार्थनाएँ सीधे भगवान तक पहुँचती हैं। विशेषकर जब साधक संतान की कामना से भरे हृदय के साथ शिव-पार्वती का आह्वान करते हैं, तो उनका संकल्प अधिक प्रभावकारी हो जाता है। ऐसे ही समय में दो पवित्र स्तोत्रों का पाठ संतान सुख के द्वार खोलने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है—संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र और अभिलाषाष्टक स्त्रोत। गणपति वह शक्ति हैं जो जीवन से विघ्न दूर करते हैं। उनका स्मरण एक नए आरंभ का संकेत है। संतान सुख भी एक नई यात्रा ही तो है—एक नए जीवन का जन्म, एक नए अध्याय की शुरुआत। इसलिए संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र का पाठ मानो जीवन में एक दिव्य बीज बोने जैसा है, जो ईश्वर की कृपा से धीरे-धीरे अंकुरित होकर फल देता है।

अभिलाषाष्टक स्त्रोत साधारण प्रार्थना नहीं है—यह वह विनम्र निवेदन है जो साधक की सभी इच्छाओं को भगवान शिव के चरणों में रख देता है। इसमें भाव होता है, surrender होता है, और एक अदृश्य विश्वास जो कहता है कि भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं। सावन सोमवार के दिन जब यह स्त्रोत शांत मन और गहरी श्रद्धा से पढ़ा जाता है, तो माना जाता है कि शिव स्वयं उस अभिलाषा को स्वीकार करते हैं और मनोकामना को पूरा करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करते हैं।

पूजा में महत्त्व केवल विधि का नहीं, भाव का होता है। यदि मन निर्मल हो, भाव सच्चे हों और विश्वास अडिग हो, तो एक बेलपत्र भी शिव के हृदय तक पहुँच जाता है। माता पार्वती स्नेह की मूर्ति हैं—उनके सामने रखा गया प्रण दंपति के जीवन में मातृत्व की ऊर्जा को जगाने लगता है। पति-पत्नी जब एक साथ पूजा करते हैं, तो उनकी संयुक्त प्रार्थना अधिक प्रभावी बनती है, क्योंकि संतान सुख स्वयं एक संयुक्त इच्छा है, एक संयुक्त भविष्य है, एक संयुक्त वरदान है। सावन सोमवार की रात को जब आसमान पर हल्का-सा बादल तैरता है और दूर से कहीं मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती हैं, तो ऐसा लगता है कि संसार ठीक इसी क्षण किसी अदृश्य ऊर्जा से भर रहा हो। ऐसे समय में किया गया स्तोत्र-पाठ केवल शब्द नहीं रहता, वह एक पुल बन जाता है मनुष्य और ईश्वर के बीच।

अनेक परिवारों की कहानियाँ ऐसी हैं जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इसी भक्ति और इसी स्तोत्र के कारण संतान सुख से धन्य हुए। कई दंपतियों ने कहा कि उन्होंने सावन सोमवार को शिवलिंग के सामने खड़े होकर बस एक बार मन से प्रार्थना की थी, और कुछ महीनों में उनके घर वह किलकारी गूँजी जिसकी प्रतीक्षा ने उनके जीवन को थका दिया था।

सावन का यह चमत्कारी समय हमें यही सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि स्वीकार भी है—स्वीकार कि जीवन की हर कमी ईश्वर के आशीर्वाद से पूरी हो सकती है। जो दंपति अपनी आशा को भक्ति में बदल देते हैं, उनके लिए संतान सुख केवल इच्छा नहीं रहता, वह ईश्वर का दिया हुआ वरदान बन जाता है।

सावन की पवित्र वर्षा में जब मन की प्रार्थना ऊपर उठती है, तो वह खाली नहीं जाती। ईश्वर सुनते हैं, समझते हैं और समय आने पर जीवन में वह खुशी भेजते हैं जो हर घर को पूर्णता का स्पर्श देती है—वह छोटी-सी किलकारी, जो आते ही पूरी दुनिया बदल देती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

राज्य सरकार का बारहवाँ चिंतन शिविर : धरमपुर, दूसरा दिन

सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास की मंशा साकार करने वाले पाँच ग्रुप डिस्कशन्स में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा मंत्रीगण सहभागी हुए

विकसित गुजरात के लिए क्षमता निर्माण, पोषण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सेवा क्षेत्र में गुजरात को 2047 तक और सुदृढ़ बनाकर विकसित भारत@2047 के लिए अग्रसर रखने का सामूहिक मंथन हुआ

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार का तीन दिवसीय बारहवाँ चिंतन शिविर वलसाड जिले के आदिजाति बहुल क्षेत्र धरमपुर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आयोजित हो रहा है।

सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास के ध्येय के साथ आयोजित हो रहे इस चिंतन शिविर के शुक्रवार को दूसरे दिन के पहले सत्र के ग्रुप डिस्कशन्स में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, मंत्रीगण तथा मुख्य सचिव श्री एम. के. दास सहभागी हुए।

विकसित गुजरात के लिए क्षमता निर्माण तथा व्यक्तिगत कामकाज मूल्यांकन, संवर्गों के पुनर्गठन तथा निरंतर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने जैसे विषयों पर आयोजित चर्चा सत्रों में कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, श्रम एवं कौशल विकास मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया, कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमलभाई छांगा, शिविरार्थी सचिवों, जिला कलेक्टरों, जिला विकास अधिकारियों तथा सुपर न्युमरी असिस्टेंट कलेक्टरों ने विकसित गुजरात@2047 के लिए गुजरात की स्थापना के 2035 में मनाए जाने वाले 75वें स्थापना दिवस तक के पिछले एक दशक में क्षमता निर्माण से राज्य को मानव संसाधन विकास और वर्कफोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के प्लेटफॉर्म प्रदान कर भविष्योन्मुखी टेक्नोलॉजी से सज्ज मानव बल तैयार करने की दिशा में चिंतन किया।

पोषण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चर्चा सत्र में सहभागियों ने राज्य में माता मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर, एनीमिया एवं पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में वेस्टिंग, अंडरवेट तथा स्टंटिंग में राज्य की स्थिति और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ऐसे प्रभावितों को देकर उनकी पोषण स्थिति सुधारने के लिए ढाँचागत सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, टेक्नोलॉजी आधारित सुधारों, महत्वपूर्ण सूचकांकों पर फोकस करने जैसे जन सुख-समृद्धि को छूने वाले विषयों पर चर्चा की।

इस सत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री प्रद्युमन वाजा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल्लभाई पानशेरिया, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री श्री स्वरूपजी ठाकोर तथा आईएएस अधिकारी सहभागी हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2070 तक नेट जीरो तथा 2030 तक 500 गीगावाट नॉन-फोसिल ऊर्जा के उपयोग सहित मिशन लाइफ तथा एक पेड़ माँ के नाम जैसे पर्यावरणोन्मुखी विचार दिए हैं।

हरित ऊर्जा तथा पर्यावरण में ग्रीन पावर के उपयोग सत्र में प्रधानमंत्री के विचारों को अधिक से अधिक ग्रीन एनर्जी के उत्पादन तथा उपयोग एवं गवर्नेंस में ग्रीन एनर्जी से पर्यावरण संरक्षण की मौजूदा कार्ययोजना तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं विश्वसनीयता तथा क्लाइमेट चेंज के प्रभावों, सर्कुलर इकनॉमी पर गहन चिंतन-मंथन किया गया।

इस चर्चा सत्र में ऊर्जा मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया, जल संसाधन एवं जलापूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल, राज्य मंत्री डॉ. मनीषा वकील, श्री कौशिकभाई वेकरिया, श्री प्रवीणभाई माली तथा आईएएस अधिकारी सहभागी हुए।

शिविर में आयोजित सार्वजिक सुरक्षा (पब्लिक सेफ्टी) के चर्चा सत्र में सड़कों, पुलों, सरकारी भवनों जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर में नागरिक सुरक्षा के लिए कार्यक्षम तथा विश्वसनीय स्ट्रक्चर्स, जलापूर्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीवेज व्यवस्था की पुनर्स्थापना, फायर सेफ्टी तथा इमर्जेंसी सर्विसेज जैसे लोगों को व्यापक रूप से स्पर्श करने वाले विषयों में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ट्रांसपरेंसी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जागृति अभियान जैसे आयोजनों की वर्तमान स्थिति तथा भविष्योन्मुखी आयोजनों के संबंध में ग्रुप डिस्कशन किया गया।

इस चर्चा सत्र में आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल, शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिला कलेक्टर तथा जिला विकास अधिकारी सहभागी हुए।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि एवं विविधीकरण से जुड़े चर्चा सत्र में रोजगार, आईटी तथा आईटीईएस सेक्टर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, वित्तीय सेवाओं, उत्पादन संबंधी सेवाओं, बंदरगाह संचालित सेवाओं, गिग, केयर तथा ग्रीन इकोनॉमी से जुड़ी सेवाओं में वर्तमान क्षेत्रीय परिदृश्य तथा इस क्षेत्र में की गई प्रमुख पहलों और भावी आयोजन से गुजरात को सेवा क्षेत्र में भी अग्रिम बनाने की दिशा में इस सत्र में सहभागी हुए सभी ने अपने सुझाव दिए तथा मत व्यक्त किए। इस चर्चा सत्र में वित्त एवं शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई, खेल राज्य मंत्री डॉ. जयरामभाई गामित, वित्त राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा, आदिजाति विकास राज्य मंत्री श्री पी. सी. बरंडा, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा तथा मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया सहभागी हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत@2047 का जो संकल्प दिया है, उसे बारहवें चिंतन शिविर के दूसरे दिन के ये चर्चा सत्र विकसित गुजरात से पूरा करने के लिए और गति देंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने धरमपुर में 'वोकेलशनल ट्रेनिंग सेंटर' का दौरा किया : वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मुख्यमंत्री का अभिवादन समारोह आयोजित

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में पीपीपी मोड पर 8 अत्याधुनिक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए
- दो दशक पहले अंबाजी से उमरगाम तक के आदिवासी बेल्ट में एक भी साइंस कॉलेज नहीं था, जबकि आज दो दर्जन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज संचालित हैं

- **मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए**
- **कौशल, नवाचार और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, भारत के युवाओं में ये तीनों गुण और क्षमताएं मौजूद हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**
- **भाग के साथ पीपीपी मोड से जुड़ा प्रमुख स्वामी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, मुख्यमंत्री ने जनभागीदारी के क्षेत्र में जुड़ाव का प्रमाण पत्र प्रदान किया**

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को धरमपुर में 'प्रमुख स्वामी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर-पीएसवीटीसी' का दौरा कर प्रशिक्षु विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

प्रमुख स्वामी महाराज की जयंती के अवसर पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की ओर से मुख्यमंत्री का अभिवादन समारोह आयोजित किया गया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और करुणा के सद्गुणों का संदेश फैलाया है। इतना ही नहीं, स्वामीनारायण संप्रदाय ने भारतीय ऋषि संस्कृति को बचाने का भगीरथ कार्य किया है। उन्होंने युवाओं को व्यसन मुक्त और सुसंस्कारी के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्षों से महाअभियान चला रहे स्वामीनारायण संप्रदाय की सराहना की।

उन्होंने कहा कि कौशल, नवाचार और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। भारत के युवाओं में मौजूद इन तीनों गुणों और क्षमता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि हमारा युवा 'स्किल, विल और जील' यानी कौशल, इच्छाशक्ति और जोश के बल पर पत्थर से भी पानी निकालने में समर्थ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दशक पहले अंबाजी से उमरगाम तक के आदिवासी बेल्ट में एक भी साइंस कॉलेज नहीं था, जबकि आज पिछले दो दशकों में दो दर्जन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज कार्यरत हैं। आज इन क्षेत्रों में शिक्षा, सुविधाओं, योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में पीपीपी मोड पर 8 अत्याधुनिक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, साथ ही तीन लाख से अधिक आदिवासी युवाओं को ऐसे सेंटरों, आईटीआई और केवीके के जरिए प्रशिक्षण और प्लेसमेंट मिला है। आदिवासी क्षेत्र धरमपुर में संचालित प्रमुख स्वामी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इसका उत्तम उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने डिग्री-आधारित नौकरी की आशा में निर्भर रहने के बजाय युवाओं को कौशल विकास की राह दिखाई है। इस अभिनव मार्ग ने लाखों युवाओं को दक्ष और कार्यकुशल बनाया है। धरमपुर पीएसवीटीसी में लगभग 30 विभिन्न ट्रेड्स कार्यरत हैं, जिनमें से इस संस्थान के शुरुआती तीन वर्षों में ही 500 से अधिक प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर बनने का अनुरोध करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। आप सभी के सहयोग से यह संकल्प पूरा होकर रहेगा।

आदिजाति मंत्री श्री नरेशभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान आदिवासी समाज के विकास के लिए वनबंधु कल्याण योजना लागू की, जिसके परिणामस्वरूप आदिवासियों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के युवाओं को पायलट, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार की सहायता से आदिवासी समाज के युवा पायलट बनकर आकाश में उड़ान भर रहे हैं।

वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अनेक योजनाएं लागू कर आदिवासी समाज के उत्थान और विकास की प्रतिबद्धता दिखाई है। इस अवसर पर सांसद श्री धवल पटेल, विधायक श्री अरविंद पटेल, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, तीर्थल बीएपीएस के कोठारी स्वामी पू. विवेक स्वरूपजी, पू. चिन्मय स्वामी, कलेक्टर भव्य वर्मा, जिला संगठन प्रमुख श्री हेमंत कंसारा सहित कई अग्रणी, विद्यार्थी और नगरजनों सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल द्वारा बाल मंदिर एवं किड्स हट स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 26 नवंबर 2025 एवं 28 नवंबर 2025 को क्रमशः किड्स हट एवं बाल मंदिर स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविरों का सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य विद्यालयीन विद्यार्थियों के संपूर्ण स्वास्थ्य मूल्यांकन तथा प्रारंभिक अवस्था में रोग पहचान कर उचित परामर्श प्रदान करना था। पहला स्वास्थ्य शिविर 26 नवंबर, 2025 को किड्स हट स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें 170 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इनमें से 20 बच्चों में दांतों में कैविटी, 01 बच्चे में बुखार तथा 01 बच्चे में खांसी की शिकायत दर्ज की गई। दूसरा स्वास्थ्य शिविर 28 नवंबर, 2025 को बाल मंदिर स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें 92 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इनमें से 15 बच्चों में दांतों की कैविटी, 02 बच्चों में कान संबंधी समस्या, 01 बच्चे में आंखों की समस्या, 01 बच्चे में त्वचा संक्रमण तथा 01 बच्चे में गले का संक्रमण पाया गया।

दोनों शिविरों में पाए गए स्वास्थ्य लक्षणों के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को जागरूक किया गया तथा आगे की विस्तृत जांच एवं उपचार हेतु बच्चों को मंडल रेलवे अस्पताल, भावनगर परा (DRH BVP) में परामर्श हेतु सुझाव दिया गया। इस स्वास्थ्य शिविर के चिकित्सा दल में डॉ. संदीप – DMO, BVP एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. निमेष एवं उनकी चिकित्सकीय टीम शामिल रही।

इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO), भावनगर मंडल की अध्यक्ष – श्रीमती शालिनी वर्मा, सेक्रेटरी – श्रीमती माया त्रिपाठी, सांस्कृतिक इंचार्ज – श्रीमती वाणी मैडम, ट्रेजरर – श्रीमती वंदना पाटीदार, किड्स हट स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती भाविका शुक्ल, बाल मंदिर स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती रूपल चूड़ासमा, श्री ब्रिजेश पटेल (वेलफेयर इंस्पेक्टर-भावनगर मंडल) एवं समिति के सदस्य का विशेष सहयोग रहा।

इन शिविरों के सफल आयोजन से विद्यालयीन विद्यार्थियों में स्वास्थ्य चेतना को बढ़ावा मिला तथा प्रारंभिक स्तर पर पहचानी गई कई स्वास्थ्य समस्याओं के शीघ्र उपचार का मार्ग प्रशस्त हुआ। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण समिति ने भविष्य में भी इसी प्रकार के कल्याणकारी एवं स्वास्थ्य संवर्धनात्मक कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

ट्रेन में हुए स्टोन पेल्टिंग मामले का सफल खुलासा - एक नाबालिग बालक की पहचान

(जीएनएस)। 24 नवंबर, 2025 को रीबड़ा – भक्तिनगर रेल सेक्शन के मध्य चल रही सवारी गाड़ी संख्या 19119 (गांधीनगर कैपिटल – वेरावल एक्सप्रेस) के ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंके जाने से उन्हें चोट आई तथा ट्रेन को रीबड़ा स्टेशन पर 06 मिनट एवं गोंडल स्टेशन पर 07 मिनट विलंब हुआ। इस संबंध में RPF जूनागढ़ द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

मामले के त्वरित खुलासे हेतु निरीक्षक जूनागढ़, निरीक्षक क्राइम ब्रांच भावनगर तथा SIB/JND की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम द्वारा 25 नवंबर 2025 को घटनास्थल के आसपास गहन पूछताछ एवं गुप्त निगरानी की गई। इस दौरान रेलवे लाइन से लगभग 50–60 मीटर दूरी पर तीन बालक संदिग्ध रूप से घूमते पाए गए।

पूछताछ में एक बालक सुशांत कुमार पुत्र पिंटू मंडल, आयु 13 वर्ष, निवासी बुध नगर, गली नंबर 3, शापर, राजकोट द्वारा 24 नवंबर 2025 को अपने दो साथियों के साथ पटरियों के पास पत्थर फेंकने तथा ट्रेन गुजरते समय अंतिम डिब्बे पर पत्थर मारने की बात स्वीकार की गई। बालकों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में पुनः पूछताछ की गई तथा घटनास्थल पर ले जाकर पुष्टि की गई। इसके पश्चात आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उक्त नाबालिग को बाल संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर अभिभावकगण के सुपुर्द किया गया।

रेलवे की अपील

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा की रेलवे संपत्ति एवं रेल परिचालन में बाधा डालना दंडनीय अपराध है। रेलवे प्रशासन आम नागरिकों से अपील करता है कि रेल पटरियों के आसपास बच्चों को खेलने न दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 या नजदीकी RPF/GRP पोस्ट पर दें।

दो वर्षों में 13.5 लाख से अधिक पर्यटकों ने शिवराजपुर बीच का किया दीदार

- **शिवराजपुर गुजरात का पहला 'ब्ल्यू फ्लैग' बीच, साफ पानी और स्कूबा डाइविंग के लिए लोकप्रिय स्थल**
- **वीजीआरसी के आयोजन से शिवराजपुर और स्थानीय पर्यटन क्षेत्र के महत्व को उजागर किया जाएगा**

(जीएनएस)। गांधीनगर : श्री कृष्ण नगरी द्वारका से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवराजपुर समुद्र तट अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय फलक पर चमक उठा है। यह बीच स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। वर्ष 2023 और 2024 में 13 लाख 58 हजार से अधिक सैलानी शिवराजपुर बीच को देखने के लिए पहुंचे। इस प्रकार स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन देकर गुजरात का पर्यटन क्षेत्र राज्य के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है और राज्य की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

गुजरात पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) के अनुसार, वर्ष 2023 में 6,78,647 और 2024 में 6,80,325 पर्यटकों ने शिवराजपुर समुद्र तट के दीदार किए। 2020 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त होने के बाद शिवराजपुर बीच गुजरात का पहला ब्लू फ्लैग बीच बन गया है। यह प्रमाण पत्र पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और सेवाओं सहित कुल 32 मानकों के आधार पर दिया जाता है। यहां स्कूबा डाइविंग, बोटिंग और जेट स्कीइंग जैसी स्पोर्ट्स गतिविधियों की सुविधाएं भी उपलब्ध है।

शिवराजपुर की सफलता 'देखो अपना देश' पहल के साथ सुसंगत है। इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी, 2020 में की थी, जिसका उद्देश्य पांच श्रेणियों के अंतर्गत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। इन पांच श्रेणियों में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत, प्रकृति एवं वन्यजीव, एडवेंचर और अन्य शामिल हैं। इस देशव्यापी अभियान को आगे बढ़ाने में शिवराजपुर समुद्र तट का महत्वपूर्ण योगदान है।

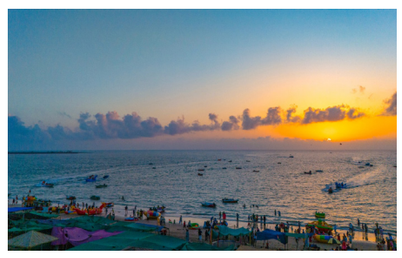

राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ी पहलें भी शुरू की हैं। क्षेत्र-विशिष्ट निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण 8-9 जनवरी को राजकोट में आयोजित होगा, जो कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र पर केंद्रित होगा। इस कॉन्फ्रेंस में शिवराजपुर जैसे पर्यटन आकर्षणों को उजागर किया जाएगा, जो दर्शाता है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करके 'विकसित गुजरात@2047' से 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

राजकोट मंडल में डबल ट्रैक कार्य के चलते रेल यातायात होगा प्रभावित

(जीएनएस)। राजकोट मंडल में स्थित लाखाबावल-पीपली-कानालुस सेक्शन में डबल ट्रैक कार्य के चलते 01.12.2025 से लेकर 15.01.2026 तक रेल यातायात प्रभावित होगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

आंशिक रूप से रद्द की गयी ट्रेनें:

ट्रेन नं 59206/59205 पोरबंदर-कानालुस-पोरबंदर लोकल 01.12.2025 से लेकर 30.12.2025 तक पोरबंदर से चलकर गोप जाम एवं गोप जाम से चलकर पोरबंदर तक जाएगी तथा गोप जाम-कानालुस के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

ट्रेनों का स्टोपेज रद्द होना:

ट्रेन नं 19209/19210 भावनगर-ओखा-भावनगर एक्सप्रेस 01.12.2025 से लेकर 15.01.2026 तक लाखाबावल और पिपली स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि वे उपरोक्त फेरबदल को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें और ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन करें ताकि किसी प्रकार कि असुविधा ना हो।

पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई सेंट्रल एवं इंदौर के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मुंबई सेंट्रल एवं इंदौर के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरों को विशेष किराये पर विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 09085/09086 मुंबई सेंट्रल – इंदौर (त्रि-साप्ताहिक) स्पेशल:

ट्रेन संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल–इंदौर स्पेशल प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 23.20 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान करती है और अगले दिन 13.00 बजे इंदौर पहुँचती है। इस ट्रेन के फेरों को 28 नवंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09086 इंदौर–मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 17.00 बजे इंदौर से प्रस्थान करती है और अगले दिन 07.10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचती है। इस ट्रेन के फेरों को 29 नवंबर से 01 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, दाहोद, रतलाम और उज्जैन स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर तथा एसी 3-टियर कोच हैं।

ट्रेन संख्या 09085 एवं 09086 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 29 नवम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पालनपुर–अहमदाबाद खंड पर स्थित जगुदन स्टेशन यार्ड में पुल संख्या 985 के पुनर्निर्माण हेतु यातायात प्रभावित

(जीएनएस)। अहमदाबाद मंडल के पालनपुर–अहमदाबाद खंड पर स्थित जगुदन स्टेशन यार्ड में अप मेन लाइन पर किलोमीटर 727/23-25 के बीच स्थित पुल संख्या 985 के पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य कट-एंड-कवर पद्धति से तथा रोड क्रेन द्वारा प्रीकास्ट आरसीसी बॉक्स स्थापित कर किया जा रहा है। सुरक्षा एवं आवश्यक इंजीनियरिंग कार्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30 नवम्बर 2025 (रविवार) को निम्नलिखित यात्री ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त तथा पुनर्निर्धारित किया गया है:

1. आंशिक रूप से निरस्त ट्रेने

- ट्रेन संख्या 20960 वडनगर – वलसाड एक्सप्रेस दिनांक 30.11.2025 को वडनगर – गांधीनगर कैपिटल के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
- ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर – साबरमती एक्सप्रेस दिनांक 30.11.2025 को आबू रोड – साबरमती के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
- ट्रेन संख्या 14822 साबरमती – जोधपुर एक्सप्रेस दिनांक 01.12.2025 को साबरमती – आबू रोड के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
- ट्रेन संख्या 20959 वलसाड – वडनगर एक्सप्रेस दिनांक 30.11.2025 को गांधीनगर कैपिटल – वडनगर के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

2. पुनर्निर्धारण

- ट्रेन संख्या 20485 जोधपुर – साबरमती एक्सप्रेस दिनांक 30.11.2025 को जोधपुर से 02.00 घंटे की देरी से रवाना होगी।
- ट्रेन संख्या 69207 गांधीनगर कैपिटल – वरेठा एक्सप्रेस दिनांक 30.11.2025 को गांधीनगर कैपिटल से 01.00 घंटे की देरी से रवाना होगी।
- ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

चिंतन शिविर-2025, धरमपुर, वलसाड

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की गुजरात को मेजबानी मिलने पर ऐतिहासिक सफलता का चिंतन शिविर में हर्षोल्लासपूर्वक स्वागत किया गया

▸▸ ढोल–नगाड़े, आतिशबाजी तथा गाजे–बाजे के बीच मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ऊष्मापूर्ण स्वागत किया गया

▸▸ मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने एक-दूसरे का मुँह मीठा कराकर हर्ष व्यक्त किया

▸▸ श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि कोई देश यदि कर सकता है, तो भारत भी कर ही सकता है; इसी विश्वास से आज हम हर क्षेत्र में दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं : मुख्यमंत्री

▸▸ श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 वर्ष पहले जो परिश्रम किया था, उसका फल आज हमें मिला है : उप मुख्यमंत्री

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर इस ऐतिहासिक सफलता का धरमपुर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आयोजित 'सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास की ओर' थीम आधारित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप-मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की गरिमामय उपस्थिति में हर्षोल्लासपूर्वक स्वागत किया गया।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के आयोजन की बोली में भारत को मिली जीत के चलते गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर इस अविस्मरणीय घड़ी का स्वागत करने के लिए आश्रम के पैवेलियन में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के पहुँचते ही ढोल-नगाड़ों की गूँज, आतिशबाजी तथा गाजे-बाजे के साथ ऊष्मापूर्ण स्वागत किया गया।

स्कूल के विद्यार्थियों ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुत कर इस क्षण का स्वागत किया।

इस ऐतिहासिक सफलता के उत्सव का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी गुजरात को मिली, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और दूरदर्शिता का परिणाम है। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि दुनिया का कोई देश यदि कर सकता है, तो भारत भी कर ही सकता है, इसी विश्वास से आज हम हर क्षेत्र में विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी ने गेम्स के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उसी के कारण आज यह ऐतिहासिक सफलता मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों के परिणामस्वरूप कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के भारत में आयोजन को मंजूरी मिली है। उनके मार्गदर्शन में इन गेम्स द्वारा भारत की धरती पर दुनिया का स्वागत करने और देश को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए हम तैयार हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "यह भारत देश के लिए गौरव की बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ऐसे में उसके नेतृत्व का अवसर गुजरात को प्राप्त हुआ, यह गौरवशाली क्षण है। श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 वर्ष पहले जो परिश्रम किया था, उसका फल आज हमें मिला है। खेल विभाग का टीम टीमवर्क, प्रेजेंटेशन की सफलता के जरिये गुजरात और अहमदाबाद को मेजबानी मिली है, जिसके लिए सभी को अभिनंदन देता हूँ।" श्री संघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। जिस तरह कॉमनवेल्थ की मेजबानी मिली, उसी प्रकार ओलंपिक की मेजबानी भी मिले, इसके लिए प्रयास जारी हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने टीम लीडर के रूप में उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। पूरे भारत को गर्व हो, इस प्रकार गुजरात की टीम कार्य कर रही है।

इस खुशी के अवसर पर सभी ने एक-दूसरे का मुँह मीठा कराया। आतिशबाजी के साथ इस मेजबानी का धूमधाम से जश्न मनाया गया।

भारत और गुजरात का विकास आसमान की ऊँचाइयों तक पहुँचे, यह संदेश देने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा गुब्बारे उड़ाए गए।

इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, आईएएस अधिकारी उपस्थित रहें।

चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' तेज़ी से भारतीय तटों की ओर बढ़ा-तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र में ऑरेंज अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में जाने से रोकने के निर्देश

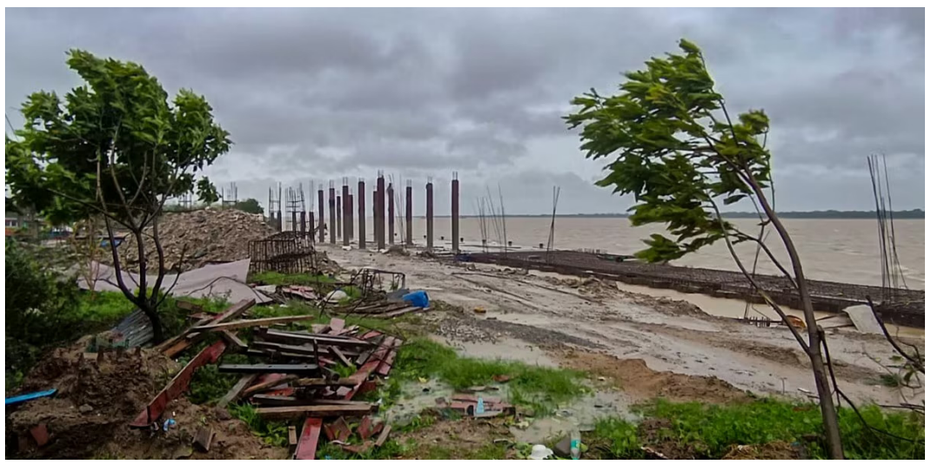

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी और श्रीलंका के तटीय इलाक़ों के पास बना चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' हर घंटे तेज़ होता जा रहा है और उत्तर की दिशा में बढ़ते हुए अब भारतीय तटों के बेहद करीब पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि यह तूफान रविवार, 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों से टकरा सकता है, जिससे कई क्षेत्रों में मूसलधार बारिश और तेज हवाओं का जोखिम बढ़ गया है।

आईएमडी के अनुसार तूफान पिछले छह घंटों में लगभग 3 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से आगे बढ़ा है। फिलहाल यह श्रीलंका के त्रिंकोमाली से महज़ 30 किलोमीटर दूर स्थित है और कराईकल से 300 किमी, पुडुचेरी से 410 किमी तथा चेन्नई से लगभग 510 किमी की दूरी पर है। विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए चक्रवात संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए स्थानीय प्रशासन और नागरिकों से पूर्ण सतर्कता बरतने की अपील की है।

आईएमडी ने अनुमान जताया है कि श्रीलंका के ऊपर से गुजरने के बाद 'दित्वाह' बंगाल की खाड़ी के गर्म समुद्री पानी में और अधिक ताकतवर हो सकता है। इसी वजह से रविवार सुबह तक इसके तट से टकराने की आशंका को गंभीर माना जा रहा है। तूफान के करीब आने के साथ हवा की रफ्तार, समुद्री लहरों की ऊंचाई और बारिश की तीव्रता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। तमिलनाडु के दक्षिणी और डेल्टा जिलों के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को डेल्टा और आसपास के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि शनिवार को उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में मूसलधार वर्षा की संभावना है। इस बीच, तटीय सुरक्षा एजेंसियों ने मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने लोगों से घरों से कम बाहर निकलने, तटीय इलाकों से दूर रहने और मौसम से जुड़ी सरकारी सूचनाओं पर लगातार नजर बनाए रखने की अपील की है। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए राहत दलों को अलर्ट पर रखा गया है और तटीय जिलों में निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है।

भारत ने तीन पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर लौटाया—लंबी सजा काटने के बाद अटारी-बाघा बॉर्डर पर पाक रेंजर्स के हवाले

(जीएनएस)। चंडीगढ़। भारत की विभिन्न जेलों में सजा पूरी कर चुके तीन पाकिस्तानी नागरिकों की घर वापसी शुक्रवार को पूरी औपचारिकता और मानवीय भावना के साथ संपन्न हुई। अटारी-बाघा बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा और आव्रजन एजेंसियों ने सभी जांच-पड़ताल पूरी करने के बाद इन कैदियों को पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया। वर्षों की कैद के बाद अपने देश लौटने की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी।

रिहा किए गए कैदियों में लाहौर के लक्खोवाल निवासी 58 वर्षीय मोहम्मद रमजान, पंजाब प्रांत के असगर अली और बड़ा पिंड के 48 वर्षीय मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। तीनों अलग-अलग मामलों में भारत की जेलों में लंबी सजा काट चुके थे। प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने बताया कि इन कैदियों को दिल्ली और राजस्थान की जेलों से अमृतसर लाया गया था। कस्टम, इमिग्रेशन और सुरक्षा जांच के बाद उन्हें औपचारिक रूप से पाकिस्तान को सौंपा गया।

मोहम्मद इकबाल की कहानी सबसे दर्दभरी है। सिर्फ 18 साल की उम्र में गुरदासपुर में 10 किलो हेरोइन के साथ पकड़े जाने पर उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत 30 साल की सजा मिली थी। इतनी लंबी उम्र जेल में बीत जाने के बाद इकबाल ने बॉर्डर पर कहा, "मेरे लिए यह दिन ईद जैसा है। 30 साल बाद घर लौटने की खुशी शब्दों में नहीं बता सकता।" उसने यह भी बताया कि गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और जेल की ज़िंदगी ने उसे भीतर तक बदल दिया है।

मोहम्मद रमजान 2010 में जम्मू के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। अदालत ने उसे साढ़े 13 साल की सजा सुनाई, लेकिन विभिन्न औपचारिकताओं के चलते वह लगभग 15 साल तिहाड़ जेल में रहा। रिहाई के बाद वह बार-बार कहता रहा कि अब वह सिर्फ अपने परिवार का चेहरा देखना चाहता है।

तीसरे कैदी असगर अली भी 2010 में समझौता एक्सप्रेस से भारत आया था, लेकिन वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद वह जोधपुर पहुंच गया, जहां उसे गिरफ्तार किया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। प्रक्रियागत देरी के कारण वह भी लगभग 15 साल कैद में रहा।

तीनों कैदियों की स्वदेश वापसी भारत-पाकिस्तान के बीच मानवीय आधार पर होने वाले सहयोग का उदाहरण है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद आज़ादी की हवा में पहली बार सांस लेते हुए सीमा पार लौटते इन कैदियों के चेहरे पर राहत, कृतज्ञता और गहरी भावनाएं साफ़ पढ़ी जा सकती थीं।

फियो ने राष्ट्रपति श्री पुतिन के दौरे के दौरान इंडिया-रूस बिज़नेस फ़ोरम से पहले विकास और अवसर पर बल दिया

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 28 नवंबर, 2025: फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (फियो) रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के 4-5 दिसंबर 2025 को होने वाले भारत के सरकारी दौरे और साथ में होने वाले इंडिया-रूस बिज़नेस फ़ोरम का स्वागत करता है, जो भारत और रूस के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग को बढ़ाने और गहरा करने के लिए सही समय पर प्लेटफ़ॉर्म है।

हाल के ट्रेड डेटा से पता चलता है कि अप्रैल-अगस्त 2025-26 के समय में रूस को भारत का निर्यात 1.84 बिलियन डॉलर था, जबकि इम्पोर्ट 26.45 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। इससे पहले रूस के साथ वस्तु व्यापार 2024-25 में रिकॉर्ड 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था, जिसमें लगभग 4.88 बिलियन डॉलर का निर्यात और 63.84 बिलियन डॉलर का आयात शामिल था। पिछले चार सालों में, 2021 से शुरू होकर, दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार पाँच गुना से ज़्यादा बढ़ा है। यह लगभग 13 बिलियन डॉलर था और 2024-25 में यह 68 बिलियन डॉलर हो जाएगा।

यह ज़बरदस्त बढ़ोतरी मज़बूत ऊर्जा और वस्तु आधारित रिश्तों को दिखाती है, लेकिन रूस के पक्ष में व्यापार असंतुलन काफ़ी बढ़ गया है। फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन का मानना है कि फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो-प्रोडक्ट्स, ऑटो और ऑटो-कंपोनेंट्स और आईटी सर्विसेज़ जैसे सेक्टर में रूस को निर्यात की बहुत संभावना है, जिनकी बदलते मार्केट डायनामिक्स के कारण बहुत ज़्यादा मांग है। श्री रल्हन ने आगे कहा कि इसके अलावा, रूस से कई पश्चिमी कंपनियों के निकलने से भारतीय निर्यातकों के लिए अलग-अलग सेक्टर में खाली जगह भरने का एक बड़ा मौका बना है। साथ ही, दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का एक बड़ा दीर्घकालिक लक्ष्य भी बताया है। फियो अध्यक्ष ने यह भी कहा कि द्विपक्षीय निवेश अभी भी काफी हैं और पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं, 2025 तक 50 बिलियन डॉलर का लक्ष्य है। भारत में रूस का निवेश ऑयल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, बैंकिंग, रेलवे और स्टील जैसे सेक्टर में है, जबकि रूस में भारत का निवेश मुख्य रूप से ऑयल और गैस और फार्मास्यूटिकल्स में है।

श्री रल्हन ने कहा कि इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) जैसे लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के फिर से शुरू होने और बढ़ने से भी देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार ज़्यादा किफायती हुआ है। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रपति श्री पुतिन के दौरे के दौरान होने वाला इंडिया-रूस बिज़नेस फोरम, भारतीय निर्यातकों, निवेशकों और रूसी निवेशकों के लिए ऊर्जा पर आधारित व्यापार से ज़्यादा डायवर्सिफाइड, स्थायी व्यापार और इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप की ओर बढ़ने का एक अहम मौका है।

फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा "यह बिज़नेस फ़ोरम भारत-रूस व्यापार के लिए एक अहम समय पर हो रहा है। जहाँ व्यापार की मात्रा में बढ़ोतरी हमारे आर्थिक संबंधों की मज़बूती दिखाती है, वहीं अब हमें इस रफ़्तार का फ़ायदा उठाकर नॉन-ऑयल सेक्टर — इंजीनियरिंग सामान, केमिकल, फ़ार्मास्यूटिकल्स, खेती, कपड़ा, चमड़ा, जेम्स और ज्वेलरी और वैल्यू-एडेड मैन्युफ़ैक्चर्ड सामान में डायवर्सिफ़ाई करना चाहिए। फ़ोरम को बैलेंस्ड, लंबे समय के व्यापार और आपसी निवेश का रास्ता बनाना चाहिए।"

फियो को उच्च मूल्य वाली वस्तुओं फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, साथ ही सेवाओं (आईटी/आईटीईएस, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा) के भारतीय निर्यात के विस्तार में विशेष रूप से मजबूत संभावनाएं दिखती हैं, साथ ही भारत के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, हरित ऊर्जा, रेलवे, खनन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रूसी निवेश को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, संस्थागत सुविधा और द्विपक्षीय व्यापार मिशनों के साथ रूस को एक बाजार के रूप में तलाशने के लिए एमएसएमई , निर्यातकों और एसएमई का समर्थन करने से भारत के निर्यात सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा।

फियो ने मरीन प्रोडक्ट्स, डेयरी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे खास सेक्टर में भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली बाजार पहुंच की चुनौतियों को दूर करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है। फेडरेशन इस बात पर ज़ोर देता है कि इन श्रेणियों की रूसी बाजार में मज़बूत और लगातार मांग बनी हुई है, और रूस की तरफ से रेगुलेटरी और प्रक्रियागत रुकावटों को दूर करने को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है जो अभी उनके प्रवेश को सीमित करती हैं। इन उच्च संभावना वाली उत्पाद श्रेणियों के लिए आसान एक्सेस को सुगम बनाते हुए, फियो अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि इससे न सिर्फ़ द्विपक्षीय व्यापार को विविधीकृत और पुनर्संतुलित करने में मदद मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने में भी मदद मिलेगी।

अमेरिका से 39 बांग्लादेशी निर्वासित: विशेष सैन्य विमान से ढाका पहुँचे, कुल संख्या 220 के पार—अवैध प्रवासन तंत्र पर गंभीर सवाल

(जीएनएस)। ढाका का हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुरुवार तड़के अचानक हलचल से भर गया, जब एक विशेष अमेरिकी सैन्य विमान सुबह लगभग साढ़े पाँच बजे उतरा और उसमें सवार 39 बांग्लादेशी नागरिक अपने देश लौटाए गए। जैसे ही विमान के दरवाज़े खुले, एयरपोर्ट प्राधिकरण और सामाजिक संस्था बीआरएसी के अधिकारी इन लोगों की व्यवस्था संभालने में जुट गए—थके चेहरों पर घर लौटने की राहत और लंबी यात्रा की चिंता दोनों एक साथ साफ दिखाई दीं।

वापस भेजे गए लोगों में 26 केवल नोआखली जिले के हैं, जबकि बाकी कुमिला, सिलहट, फेनी, लक्ष्मीपुर, चटगांव, गाज़ीपुर, ढाका, मुंशीगंज और नारायणगंज जैसे इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। द डेली स्टार की रिपोर्ट बताती है कि 2024 से अगस्त 2025 तक 220 से अधिक बांग्लादेशी अमेरिका से निर्वासित किए जा चुके हैं—यह संख्या अब बांग्लादेशी प्रवासन तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बीआरएसी के प्रवासन कार्यक्रम प्रमुख शरीफुल हसन ने इन मामलों में भारी अव्यवस्था और खराब समन्वय पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन लोगों को आधिकारिक तौर पर श्रमिक के रूप में विदेश जाने की अनुमति दी, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया कि वे वास्तव में निर्धारित देश जा रहे हैं या अमेरिका पहुँचने के लिए ब्राजील–मेक्सिको–यूएस के अवैध मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने जिन एजेंसियों ने मंजूरी दी, उन्हें जवाबदेह ठहराने की मांग भी उठाई।

दस्तावेजों से चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया—220 में से 34 लोग BMET (Bureau of Manpower Employment & Training) की मंजूरी लेकर ब्राजील गए, जहाँ से वे मेक्सिको पहुँचे और फिर बिना वैध कागज़ातों के अमेरिका में दाखिल होने का जोखिम उठाया। बाकी में से दो सीधे अमेरिका पहुँचे, जबकि तीन ने दक्षिण अफ्रीका के रास्ते की बेहद खतरनाक यात्रा की। सबसे दर्दनाक खुलासा उन लोगों ने किया जिन्हें अमेरिका ने वापस भेजा। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में कई बांग्लादेशियों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ पहनाकर निर्वासित किया गया—हालाँकि वे खुद ऐसी स्थिति से बच निकलने पर राहत महसूस कर रहे थे। इससे पहले भी 8 जून को एक चार्टर्ड विमान से 42 लोगों को ढाका भेजा गया था और 6 मार्च से 21 अप्रैल के बीच 34 और लोगों को अलग-अलग उड़ानों से निर्वासित किया गया था।

तेजी से बढ़ती यह संख्या न केवल अवैध प्रवासन की खतरनाक प्रवृत्ति, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेशी प्रवासियों की स्थिति को लेकर भी गंभीर चिंताएँ पैदा कर रही है। सवाल साफ है—लोग कौन-सी मजबूरी में जोखिम उठाकर इन खतरनाक रास्तों पर निकल रहे हैं, और बांग्लादेश का प्रवासन ढाँचा किस हद तक इसे रोकने में नाकाम है?

पश्चिम रेलवे पर रविवार, 30 नवम्बर, 2025 को दिवसकालीन ब्लॉक नहीं

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे का मुंबई सेंट्रल एवं माहिम स्टेशनों के बीच रात्रिकालीन ब्लॉक रेल पथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा शनिवार/रविवार अर्थात 29/30 नवम्बर, 2025 के बीच की मध्यरात्रि को 00.15 बजे से 04.15 बजे तक मुंबई सेंट्रल एवं माहिम स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइन पर 4 घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जायेगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ब्लॉक अवधि के दौरान फास्ट लाइन की सभी ट्रेनों का परिचालन सांताक्रुज़ एवं चर्चगेट स्टेशनों के बीच धीमी लाइनों पर किया जाएगा।

इस ब्लॉक की विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त ब्लॉक व्यवस्था को ध्यान में रखें।

इसके फलस्वरूप पश्चिम रेलवे उपनगरीय खंड पर रविवार, 30 नवम्बर, 2025 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

पश्चिम रेलवे 30 नवंबर, 2025 को मुंबई साइक्लोथॉन के लिए दो स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाएगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे मुंबई साइक्लोथॉन 2025 के प्रतिभागियों की सुविधा के लिए 30 नवंबर, 2025 को विरार से बांद्रा के लिए 01.30 बजे और 03.00 बजे दो स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाएगी। साइक्लोथॉन के प्रतिभागियों को नीचे दी गई स्पेशल ट्रेनों में साइकिल ले जाने की इजाजत होगी। इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैं:

दिनांक 29 नवम्बर 2025 से 1 दिसम्बर 2025 तक रेलवे क्रॉसिंग संख्या 29 C (अहमदपुरा फाटक) बंद रहेगा

(जीएनएस)। अहमदाबाद मंडल के नांदोल दहेगाम–रखीयाल सेक्शन के बीच स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग संख्या 29 C (अहमदापुरा फाटक) पर रख-रखाव, रबराइजेशन तथा ओवरहॉलिंग कार्य के लिए 29 नवम्बर 2025 को प्रातः 09:00 बजे से 01 दिसम्बर 2025 को सायं 19:00 बजे तक बंद रहेगा।

ईस अवधि के दौरान मार्ग सुरक्षा एवं कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए संबंधित मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान सड़क यातायात को अहमदपुरा गाँव रेलवे ब्रिज LHS-24 B, नांदोल दहेगाम रेलवे स्टेशन फाटक 28 B, दहेगाम–गांधीनगर रोड अंडर ब्रिज-20 A वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा।

दिनांक 29 नवंबर 2025 से 08 दिसंबर 2025 तक केवल रात्रि 23.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक शाहीबाग अंडरपास यातायात हेतु बंद रहेगा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर स्थित अंडरपास संख्या 731 A (कि.मी. 498/28-30), शाहीबाग अंडरपास, दिनांक 29 नवंबर 2025 से 08 दिसंबर 2025 तक केवल रात्रि 23.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के कारण यातायात हेतु बंद रहेगा। सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए इस अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्ग निम्नानुसार रहेगा :

1.दिल्ली दरवाजा और सुभाषब्रिज की ओर से आने वाला ट्राफिक, जो एयरपोर्ट-गांधीनगर की ओर जाना चाहता है, वह वाहन सुभाषब्रिज के अंत में शिलालेख फ्लैट से होकर रिवरफ्रंट का उपयोग करके रिवरफ्रंट रोड डफनाला से होकर एयरपोर्ट और गांधीनगर की ओर आवागमन कर सकेंगे।

2.एयरपोर्ट-गांधीनगर से आने वाला ट्राफिक डफनाला रिवरफ्रंट का इस्तेमाल कर अलग-अलग मार्गो पर जा सकता है। इसके अलावा असारवा, गिरधरनगर, दिल्ली दरवाजा, कालूपुर की ओर जाने के लिए शाहीबाग के रास्ते महाप्रज्ञजी ब्रिज का उपयोग करके मुख्य सड़कों पर जा सकेंगे।

अलास्का की धरती फिर कांपी: 6.0 तीव्रता के भूकंप ने थैंक्सगिविंग की सुबह जगाया, पर बड़ी तबाही से बचा प्रदेश

(जीएनएस)। अलास्का का आसमान सामान्य था, बर्फीली हवाएँ वैसे ही बह रही थीं, लेकिन गुरुवार की सुबह 8 बजकर 11 मिनट पर धरती ने एक बार फिर अपने अंदर की बेचैनी बाहर उगल दी। दक्षिण-मध्य अलास्का का एंकोरेज महानगरीय क्षेत्र अचानक जोर से हिल उठा। अमेरिकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने तुरंत ही पुष्टि की कि भूकंप की तीव्रता 6.0 थी और इसका केंद्र विलो से लगभग 26 मील दक्षिण-पश्चिम तथा करीब 43 मील की गहराई में था। थैंक्सगिविंग की शांत सुबह अचानक डर और घबराहट में बदल गई। कई घरों में लोग नींद में थे, कई अपने त्योहार की तैयारियों में लगे हुए थे—और तभी दीवारें चरमराईं, शेल्फ़ें हिलने लगीं, और बर्तन तथा सजावटी सामान गिरने की आवाज़ हर घर में गूंज उठी।

अलास्का डेली न्यूज़ की रिपोर्ट बताती है कि प्रारंभिक झटके इतने मजबूत थे कि दूर स्थित वाल्डेज और फेयरबैंक्स जैसे इलाकों में भी जमीन थरथरा उठी। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। बिजली आपूर्ति और संचार तंत्र भी अधिकतर क्षेत्रों में सामान्य बना रहा।

नेशनल सुनामी सेंटर ने भी स्पष्ट घोषणा की कि इस भूकंप से कोई सुनामी खतरा नहीं है, जिससे समुद्र किनारे बसे समुदायों ने एक लंबी सांस ली।

अलास्का के इतिहास में बड़े भूकंप कोई नई बात नहीं। भू-वैज्ञानिकों के अनुसार यह क्षेत्र दुनिया के सबसे संवेदनशील भूकंप ज़ोन में से एक है, जहां लगभग हर वर्ष 7.0 या उससे अधिक तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आने की संभावना रहती है। वर्ष 2021 के बाद यह अब तक का सबसे तीव्र भूकंप माना जा रहा है। इसके पहले 30 नवंबर 2018 का 7.1 तीव्रता वाला भूकंप पूरे क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाकर गया था—सड़कें उखड़ी थीं, इमारतें चटख गई थीं और लोग महीनों तक भय में जीते रहे थे।